**प्रधान मंत्री और अन्य नेताओं की हत्या की कथित योजना**

455. **श्री हुकम चन्द कछवाय** . क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं की हत्या करने की कोई लिखित योजना उत्तर प्रदेश के नक्सलवादी नेता श्री शिव कुमार मिश्रा की गिरफ्तारी के समय बरामद हुई थी;

(ख) यदि हा, तो सरकार की इस के बारे में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पिछले पांच महीनों मे श्री मिश्रा से जेल में भेंट करने वाले व्यक्तियो के क्या नाम हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार श्री शिव कुमार मिश्र की गिरफ्तारी के समय ऐसे कोई दस्तावेज बरामद नही किये गये । किन्तु प्रधान मंत्री तथा अन्य नेताओं के लिए सुरक्षा प्रबन्धों की आवश्यकता होने पर पुरन: परीक्षण किया जाता है और यदि अपेक्षित हो तो उन्हे सुदृढ़ किया जाता है ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है ।

**राजस्थान के बाड़मेर जिला सहकारी बैंक से दो लाख रुपये लेकर पाकिस्तान भाग जाने वाले व्यक्ति**

456. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार. राजस्थान के बाड़मेर जिला के सहकारी बैंक (राजस्थान) से लगभग दो लाख रुपया लेकर पाकिस्तान भाग गये लगभग 413 व्यक्तियों वाले मामले के सम्बन्ध में उच्चस्तरीय जांच करवाने का विचार है;

(ख) इस धनराशि की वसूली के लिये सरकार भविष्य में क्या कार्यवाही करने जा रही है;

(ग) क्या जो लोग पाकिस्तान चले गये हैं उनमें से काफी लोगों के विरुद्ध भारतीय रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमे भी दर्ज है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर जांच आयोग की स्थापना कब तक कर दी जायेगी?

**गृह मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री एफ. एच. मोहसिन)** : (क) से (घ). राजस्थान सरकार से सूचना अभी आनी है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

**Industrial Development for creating Employment Opportunities**

458. SHRI D.B. CHANDRA GOWDA :
SHRI K. LAKKAPPA :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration of Government to give priority for the industrial development to create more employment opportunities ; and

(b) if so, the broad features thereof ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) : (a) and (b) : In the process of economic development of the country, Industrial Sector has a very important role to play. The primary object of our Industrial Policy is, therefore, not only to accelerate and maximise the rate of industrial growth with a view to bringing about a rapid increase in the gross national product but also to provide gainful employment to millions of people and also to take the process of

industrial development to the semi-urban and rural areas of the country. The Industrial Policy and the Licensing Policy of the Government are fully geared to these objectives. These policies provide for a framework for a rapid and broad-based industrial growth consistent with other socio-economic objectives of the Govt. The Policy of raising the exemption limit, for the purpose of industrial licensing to Rs. 1 crore subject to certain conditions, reservation of certain industries for development exclusively in the Small Scale Sector and extending the area of such reservation and encouraging the Co-operative and Rural Industries sector have all helped to broaden the industries base and provide for increased employment opportunities.

**Shortage of Civil Engineers**

459. SHRI P. A. SAMINATHAN : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the 8th Annual Report of the Institute of Applied Manpower Research about the indication of marginal shortage of Civil Engineers by 1973-74 ; and

(b) if so, the steps taken by Government to avoid the shortage ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K C. PANT) : (a) and (b) : Yes, Sir. The Report on "Civil Engineers in India-Stock, Demand and Supply" published very recently by the Institute of Applied Manpower Research contains an assessment that by 1973-74, there will be a surplus of 3,000 civil engineering graduates and a shortage of 9,900 civil engineering diploma-holders. The shortage would be very marginal, about 6,900, in comparison to the total stock of about 1,50,000 civil engineers in the country in 1973-74. The future demand for engineers and the enrolment targets in engineering institutions are being continuously reviewed by Government, so that remedial measures can be taken in time.

**पिछड़े जिलों में लघु तथा मध्यम स्तर के औद्योगिक एककों के लिए सहायता**

460. श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव :
श्री आर. वी. बड़े :
श्री पी. नरसिम्हा रेड्डी :

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पिछड़े जिलों में नये आरम्भ हुये लघु तथा मध्यम स्तर के औद्योगिक एककों को अनुदान अथवा सहायता देने के लिये कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**औद्योगिक विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री घनश्याम ओझा)** : (क) और (ख) योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श द्वारा एक योजना तैयार कर घोषित की गई गयी है। इस योजना के अनुसार केन्द्रीय सहायता के लिए जो 50 लाख रुपये से कम अचल पूंजी विनियोजन वाले नए एककों के अचल पूंजी विनियोजन के 1/10 भाग के बराबर होगी। कुछ जिलों क्षेत्रों का चयन किया गया है। योजना आयोग का ब्यौरा 26 अगस्त 1971 के असाधारण गजट मे प्रकाशित किया गया है। जम्मु तथा काश्मीर नागालैण्ड, आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और नेफा मे स्थापित किए जाने वाले नए एककों के लिए परिवहन सहायता की भी 27 जुलाई, 1971 को घोषणा की गई है। यह सहायता कच्चे माल और इन क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले एककों द्वारा उत्पादित तैयार माल के परिवहन के लिए उपलब्ध होगी।

लगभग 200 जिलों, जिनको पिछड़े जिले की संज्ञा दी गई है, में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों के लिए रियायती दरों पर वित्त प्राप्य हैं।

इसके अलावा, विभिन्न पिछड़े क्षेत्रों में